

मुख्यमंत्री ने चैत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर आद्यशक्ति अंबाजी मंदिर में माताजी के दर्शन किए

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी में चैत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को आद्यशक्ति मां अम्बे के दर्शन किए तथा उनकी भक्तिभावपूर्वक पूजा-अर्चना की। पटेल ने आद्यशक्ति धाम अंबाजी मंदिर में शीघ्र झुका कर साढ़े छह करोड़ गुजरातियों की सुख, समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि माताजी जनहित के कार्य करने की शक्ति दें, गुजरात विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे व उत्तम से सर्वोत्तम बने। इसके लिए माताजी के कृपा-आशीर्षक बरसे रहें। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मां आद्यशक्ति के दर्शन करने के बाद अंबाजी मंदिर परिसर में एगो मॉल

का शुभारंभ कराया। उन्होंने इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा विकसित अंबाजी मंदिर की मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फ़ार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पांच लाभाधारियों को चाबियों अर्पित कीं और साथ ही विचरणशील व विमुक्त जाति की कुल 41 महिला लाभाधारियों को 80 वर्ग मीटर के प्लॉट की सनदों का वितरण भी किया। उद्देश्यपूर्ण है कि अंबाजी गांव के आसपास रहने वाली मदारी, भरथरी तथा वादी जैसी विचरणशील विमुक्त जातियों के लोगों के परिवारों के लिए 'श्री शक्ति वसाहत' (बस्ती) का निर्माण हो रहा है। इस बस्ती में सरकार के सहयोग से पक्के आवासीय मकानों

की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर सड़क एवं भवन मंत्री पूर्णेश मोदी, सांसद परबत पटेल, राज्यसभा के सदस्य दिनेश अनावाडिया, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, मुख्य सचिव पंकज कुमार, अरवली जिला कलेक्टर आनंद पटेल, अरवली जिला विकास अधिकारी स्वप्निल खरे, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के सचिव आर. आर. रावल, अरवली जिला पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाणा सहित अधिकारीगण, पदाधिकारीगण एवं लाभाधारिगण उपस्थित रहे।

सरकार के मांगों स्वीकार करने के बाद डॉक्टर ने पांच दिनों से चल रही हड़ताल खत्म

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात सरकार के मांगों स्वीकार करने के बाद डॉक्टरों ने अपनी पांच दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी और ड्यूटी पर लौट गए। बता दें कि गुजरात के सरकारी अस्पतालों में सेवारत करीब 10 हजार जितने डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर थे। सरकार को सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल खत्म होने से राज्य के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिली है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो गई थीं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने पहले भी डॉक्टरों की मांगों का निपटारा किया है और कुछ मांगों पर समय सीमा इत्यादि के मुद्दे थे, जिस पर डॉक्टरों के साथ बैठकर स्पष्टता कर दी गई है। उन्होंने कहा कि टीकू कमीशन इत्यादि के लाभ 30 तक मिलेंगे। राज्य के आयुष शिक्षकों के एनपीबीए के लिए अलग से विचार किया जाएगा। उन्होंने चार मुद्दों को लेकर स्थिति अस्पष्ट थी जिसका आज समाधान हो गया है। डॉक्टरों को सरकार पर भरोसा है कि उनकी मांगों का निश्चित समय सीमा में समाधान हो जाएगा।

केवडिया में कल से दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का आयोजन किया गया

अहमदाबाद (ईएमएस) नर्मदा जिले के केवडिया में कल से दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का आयोजन किया गया है। 9 और 10 अप्रैल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट केवडिया कॉलोनी में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का आयोजन किया गया है। 9 अप्रैल को मध्यस्थता विषय पर तीन सत्र होंगे। जबकि 10 अप्रैल को 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर दो सत्र होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के दूसरे दिन सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ 'प्युचर ऑफ जस्टिस-टेक्नोलोजी और ज्युडिशियरी' विषय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। मध्यस्थता सत्रों में वाणिज्यिक मध्यस्थता के बारे में जानकारी और उससे लाभाधारियों को होनेवाले लाभ

के साथ ही कोर्ट से जुड़ी मध्यस्थता संबंधित पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। केस दाखिल होने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया और लाभ समेत ऑनलाइन मध्यस्थता पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण उपस्थित रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कानून मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी, भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के अलावा सर्वोच्च अदालत के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी परिषद में बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगे और विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव व विचार व्यक्त करेंगे। इस परिषद के विषय मुख्य न्यायाधीश अरविंद द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद तय किए गए हैं।

गुजरात भाजपा प्रमुख ने अगले विधानसभा सत्र में पशु नियंत्रण कानून रद्द करने का दिया आश्वासन

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटील ने पशुपालकों को आश्वासन दिया है कि राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पशु नियंत्रण कानून रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य के शहरों में आवारा पशुओं के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा पशु नियंत्रण विधेयक पास किया था। विधेयक के पास होने पर पशुपालकों समेत कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि यह कानून पशुपालक विरोधी है। गुजरात के लोगों को गाय पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़े और हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़े यह उचित नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा में पशु नियंत्रण विधेयक पास होने के बाद राज्यभर में इसका कड़ा विरोध किया गया था। जिसके बाद गुजरात सरकार ने फिलहाल पशु नियंत्रण कानून का अमलीकरण स्थगित करने का फैसला किया था। लेकिन पशु नियंत्रण विधेयक स्थगित करने नहीं बल्कि इसे रद्द करने की पुरजोर मांग

के बाद सीआर पाटील ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा के आगामी सत्र में इसे रद्द कर दिया जाएगा। पाटील ने कहा कि विधानसभा सत्र पूर्ण हो चुका है, इसलिए फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। लेकिन विधानसभा के आगामी सत्र में पशु नियंत्रण कानून को रद्द कर दिया जाएगा और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी चर्चा कर ली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के लोगों को गाय पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़े और हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़े यह उचित नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा में पशु नियंत्रण विधेयक पास होने के बाद राज्यभर में इसका कड़ा विरोध किया गया था। जिसके बाद गुजरात सरकार ने फिलहाल पशु नियंत्रण कानून का अमलीकरण स्थगित करने का फैसला किया था। लेकिन पशु नियंत्रण विधेयक स्थगित करने नहीं बल्कि इसे रद्द करने की पुरजोर मांग

गुजरात हाईकोर्ट ने शहरों में गौचर जमीन की मांग करते पशुपालकों की याचिका ठुकराई

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात हाईकोर्ट ने पशुपालकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने शहरों में पशुओं के लिए गौचर जमीन की मांग की थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि पशुओं की देखभाल, उन्हें चारा देना और रहने की जगह जिम्मेदारी पशुपालकों की है। शहरों में पशुओं को छोड़ देते हैं और आवारा बनकर इधर उधर घूमता रहता है। प्लास्टिक समेत ऐसी चीजें खाते हैं जो पशुओं के हित में नहीं हैं। हाईकोर्ट को भी निर्दोष पशुओं के प्रति दया है, लेकिन पशुपालकों के प्रति नहीं। पशुपालक अपने पशुओं का उचित ध्यान नहीं रखते। पशुपालक अगर शहर में पशु रखकर दूध बेचकर रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने पशुओं के रहने और चारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में प्रत्येक पशुपालक अपने पशुओं के रहने की व्यवस्था करते हैं और अपनी जमीन में ही उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं। शहरों में जमीन का अभाव है ऐसे में पशुओं के लिए गौचर जमीन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत बड़े शहरों में लोगों को रहने के लिए 10*10 के कमरे जितनी जगह मिलना मुश्किल है, ऐसे में पशुओं के लिए गौचर जमीन की व्यवस्था कैसे होगी। यह गौचर जमीन की तो इसे घटाने या बढ़ाने का अधिकार महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा आयुक्त और नगर पालिका में मुख्य अधिकारी को है। जुर्माने की

के मामले भारी भरकम जुर्माना भरने में गरीब पशुपालक सक्षम नहीं हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पशुपालक अपने पशुओं के चारे पर एक रुपया खर्च नहीं करना चाहते। दूध दोहने के बाद पशुओं को छोड़ देते हैं और आवारा बनकर इधर उधर घूमता रहता है। प्लास्टिक समेत ऐसी चीजें खाते हैं जो पशुओं के हित में नहीं हैं। हाईकोर्ट को भी निर्दोष पशुओं के प्रति दया है, लेकिन पशुपालकों के प्रति नहीं। पशुपालक अपने पशुओं का उचित ध्यान नहीं रखते। पशुपालक अगर शहर में पशु रखकर दूध बेचकर रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने पशुओं के रहने और चारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में प्रत्येक पशुपालक अपने पशुओं के रहने की व्यवस्था करते हैं और अपनी जमीन में ही उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं। शहरों में जमीन का अभाव है ऐसे में पशुओं के लिए गौचर जमीन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत बड़े शहरों में लोगों को रहने के लिए 10*10 के कमरे जितनी जगह मिलना मुश्किल है, ऐसे में पशुओं के लिए गौचर जमीन की व्यवस्था कैसे होगी। यह गौचर जमीन की तो इसे घटाने या बढ़ाने का अधिकार महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा आयुक्त और नगर पालिका में मुख्य अधिकारी को है। जुर्माने की

रकम और पशु पंजीकरण के बारे में पशुपालक संबंधित सत्ताधीशों के समक्ष पेश करें।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आम लोगों के साथ ली चाय की चुस्की

अहमदाबाद (ईएमएस) अंबाजी धाम के निकट स्थित कोटेश्वर के ग्रामजनों और बच्चों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सहज, सरल और निश्चल व्यक्तित्व का अद्भुत अनुभव हुआ। मुख्यमंत्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद गब्बर में लाइट एंड साउंड शो सहित अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए जा रहे थे। वे रास्ते में एक आम नागरिक की तरह अचानक एक दुकान पर खड़े रह गए और एक वृद्ध व्यक्ति के साथ आत्मीयता से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। यहां मौजूद बच्चों के साथ भी उन्होंने परिवार के बुजुर्ग की तरह संवाद कर उनकी शिक्षा और स्कूल की सुविधा आदि मामलों पर प्राथमिक जानकारी हासिल की। भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीणों के साथ चाय की चुस्की ली और नास्ता भी किया। सड़क एवं भवन मंत्री पूर्णेश मोदी, राज्य मंत्री अरविंद रेयाणी और मुख्य सचिव पंकज कुमार भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे।

ज्यूरिख स्थित स्टार्टअप Sleepiz ने स्मार्ट वाई लॉन्च करने के लिए SMS अस्पताल के साथ सहयोग किया

अहमदाबाद : ज्यूरिख की मेडटेक स्टार्टअप Sleepiz (Ltd.) ने अहमदाबाद स्थित एएए अस्पताल के साथ अपनी नवीन तकनीक प्रस्तुत करने के लिए सहयोग किया है। इस तकनीक से किसी भी सामान्य वाई को स्मार्ट वाई में अपग्रेड किया जा सकता है ताकि अस्पताल में कोड ब्लू का जल्द पता लगाया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। कोड ब्लू, अस्पताल के वाई में अचानक ही मरीज की हालत बिगड़ने के संदर्भ का एक चिकित्सीय शब्द है, जो जीवन के लिए घातक क्षण है। यह दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। अस्पतालों में इनमें से अधिकांश मौतों को समय पर हस्तक्षेप करके रोका जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मैन्युअल

निगरानी प्रक्रियाओं के साथ, इन घटनाओं की समय पर सूचना प्राप्त करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। Sleepiz इन घटनाओं का जल्द पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्ट चिकित्सा उपकरणों और AI-संचालित एल्गोरिदम का उपयोग करता है। किसी मरीज की हालत बिगड़ने की स्थिति में डॉक्टरों और नर्स को उनके फोन पर रीयल-टाइम वास्तविक समय पर सूचना मिलती है। नर्स इमीडीएट रिसपॉन्स टीम तत्काल प्रतिक्रिया टीम को सक्रिय कर सकती हैं और ऐसी मौतों को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही कर सकती हैं। Sleepiz और एएए अस्पताल ने अहमदाबाद में इस नवीन तकनीक को लाने के लिए साझेदारी की है। उन्होंने केवल एक महीने में 191

समयोचित कार्यवाही के साथ 58 मरीजों का जान बचाई है। SMS अस्पताल के साथ साझेदारी का नेतृत्व करने वाले एताई के क्लिनिकल ऑपरेशन मैनेजर डॉ. रोशनी श्रीवास्तव ने कहा कि, Sleepiz One+ गैर-संपर्क तरीके से श्वसन की निगरानी के लिए दुनिया का पहला एई प्रमाणित उपकरण है। यह एकल-कृत एई2 (ऑक्सिजन सेंसर) द्वारा संचालित है और निरंतर डेटा और ट्रेंड के विश्लेषण से पूरी तरह से नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारी निरंतर मॉनिटरिंग (निगरानी) तकनीक अस्पतालों को मरीजों के लिए पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई ऐसी अभूतपूर्व देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाती है।



जल जीवन मिशन

हर घर जल

- गुजरात सरकार के दृढ़निश्चय, अटल निर्णय और आयोजन से वर्ष 2022 के अंत तक राज्य के सभी गाँवों को स्वच्छ, पर्याप्त और नियमित रूप से पानी प्राप्त होगा।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 94% से भी अधिक घरों में 'नल से जल' पहुँच रहा है।

100 प्रतिशत नल से जुड़े जिले
16

100 प्रतिशत नल से जुड़ी तहसील
150

100 प्रतिशत नल से जुड़े गाँव
15,438

ग्राम स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं के संबंध में पीने के पानी संबंधित शिकायत के लिए 24*7 टोल फ्री नंबर-1916 पर संपर्क करें